International Journal of Home Science 2019; 5(2): 211-212

ISSN: 2395-7476
IJHS 2019; 5(2): 211-212
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 09-03-2019
Accepted: 13-04-2019

पूनम पाण्डेय
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

कामिनी जैन
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत।

नीलमा कुँवर
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत।

Correspondence
पूनम पाण्डेय
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

महिला विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में सरकारी, गैर सरकारी एवं जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की भूमिका

पूनम पाण्डेय, कामिनी जैन एवं नीलमा कुँवर

सारांश
आदिवासी विकास वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। ब्रिटिश शासन में इसका महत्व कुछ भी नहीं था। स्वतन्त्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा के साथ आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास का महत्व बहुत बढ़ गया। संसदीय शासन प्रणाली में जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहता है। संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गयी है।

मूल शब्दः सरकारी, गैर सरकारी एवं जनप्रतिनिधियों

प्रस्तावना
मध्यप्रदेश में आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज रहा है लेकिन भूमि सम्बन्धी सुधारों के कारण आदिवासियों का भूमि से प्रथकीकरण हो गया। अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण इनकी कृषि भूमि या तो सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिगृहीत कर ली अथवा धनाढ्य वर्ग ने सस्ते दामें में कृषि भूमि का उपयोग उद्योगों के लिए कर लिया। मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासियों की दयनीय आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए तथा प्रदेश से इनके पलायन को रोकने के लिए शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिनन कार्यक्रमों को संचालित करने का निर्णय लिया। इन जनजातियों के विकास हेतु प्रदेश में 10 अभिकरण कार्यरत हैं एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं के अन्तर्गत 26 वृहद एवं 5 मध्यम परियोजनायें 30 मॉडल पाकेट्स एवं 6 लघु आंचल कार्यरत हैं। प्रदेश में तीन पूर्णतः अनुसूचित जनजाति जिले तथा 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड हैं। राज्य में आदिवासियों के उत्थान हेतु आदिवासी विकास निगम के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है लेकिन इन योजनाओं में शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अध्ययन पद्धति
शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश का जिला होषंगाबाद है जिसमें केसला ब्लाक के छीतापुर, चांदकिया एवं कासदाखुर्द गाँव को चयनित किया गया है। 100 महिला आदिवासी महिलायें प्रत्येक गाँव से चयनित की गयी हैं। इस प्रकार कुल 300 आदिवासी महिलाओं को चयनित किया गया है।

परिणाम

सारिणी 1: शैक्षणिक स्थिति

क0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षित	46	15.3
2.	अशिक्षित	198	66.0
3.	साक्षर	56	18.6
	कुल	300	99.9

भारत में महिलाओं में अशिक्षा सर्वाधिक है इसमें कोई दो मत नहीं है, मुख्यतः आदिवासी समुदाय जहां महिलायें और भी अधिक दीन हीन स्थिति में निवास कर रहीं है, यदि उनका शैक्षणिक स्तर देखा जाये

तो अन्य समुदाय की महिलाओं की अपेक्षा और भी में आज भी अशिक्षा विद्यमान है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी आदिवासी कल्याण योजनओं के प्रति जागरूकता, लाभ लेने की स्थिति, जीवन स्तर आदि पर दिखाई है।

सारिणी 2: आदिवासियों के लिए चलायी जा रही आर्थिक योजनाओं का उपयोग पारिवारिक सदस्यों द्वारा

क0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	178	59.3
2.	नहीं	122	40.6
	कुल	300	99.9

आदिवासी लाभार्थियों की श्रेणी में न केवल आदिवासी महिलायें आती हैं बल्कि इसके अंतर्गत आदिवासी परिवार के बच्चे, किशोरियां एवं अन्य सदस्य भी आते हैं जिनके लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। जब लाभार्थियों से यह पूछा गया कि परिवार के अन्य सदस्य इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं कि नहीं तो 59.3 प्रतिशत कहते हैं कि हाँ वहीं 40.6 प्रतिशत मानते हैं कि नहीं ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि सरकार के अथक प्रयास कल्याण योजनाओं द्वारा इनके जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है ताकि यह अपने आप को समाज के अन्य तबके के सामने अपनी दीन हीन स्थिति से उबर पायें इस हेतु लाभार्थियों को अपने परिवार की चाहर दिवारी से बाहर लाकर लाभा देने हेतु आगे आना पड़ेगा।

सारिणी 3: आदिवासियों के लिए चलायी जाने वाली योजनाएं विकास हेतु पर्याप्त

क0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	29	9.6
2.	नहीं	271	90.3
	कुल	300	99.9

शासन के द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु लम्बे समय से प्रयास किए जा रहे हैं इसके बावजूद इनका प्रभाव आज भी उनके जीवन पर कम ही दिखाई दे रहा है। इसके लिए उनके रीति रिवाज, शिक्षा का अभाव आदि जिम्मेदार है। आदिवासियों हेतु विभिनन प्रकार की कल्याणकारी योजनायें निरन्तर बनती रहीं है, आंकड़े बताते हैं कि आधिकांष लाभार्थी इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है जो भी कल्याणकारी योजनांए हैं वे ऊँट के मुंह में जीरे के समान हैं। जबतक सरकारी प्रयास और अधिक नहीं किए जाते एवं वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं प्राप्त होता यह स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व थी और आदिवासी आने वाले समय में भी लोंगों के लिए धनार्जन का कारण बनेंगें न कि धनार्जन कर पायेंगे क्योंकि अधिकांष परिवार केवल जीवनयापन करनें तक ही कमा पा रहे हैं जिसमें सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सारिणी 4: आदिवासी परियोजनाओं के कियान्वयन में अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त

क0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	207	69.0
2.	नहीं	93	31.0
	कुल	300	99.9

जब सहयोग किसी समुदाय या वर्ग को प्राप्त हो तो किसी भी समुदाय का सामना काफी हद तक किया जा सकता है क्योंकि वे सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधत्व करते हैं एवं लोगों को फिर भय नहीं होता आंकड़े भी यही स्पष्ट करते हैं कि 69.0 प्रतिशत लाभार्थी अधिक निम्न हैं आंकड़े भी यही बताते हैं कि मात्र 15.3 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, वहीं 18.6 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं वहीं 66.0 प्रतिशत महिलाओं मानते हैं कि जो भी उनके कल्याण हेतु योजनाएं चलायी जा रहीं है उन्हें अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं 31.0 प्रतिशत का मानना है कि उच्च वर्गों के द्वारा आज भी अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके कारण इसके कियान्वयन में बाधा आ रही है जिसके कारण स्वयं आदिवासी समुदाय भी प्रभावित है।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में 1987–88 में 52.6 प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे थे। आठवीं पंचवर्शीय योजना भारत सरकार के दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि आज भी हमारे देश में अधिकांश आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे हैं।

सरकार का दावा है कि सामान्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया से ही गरीबी दूर करने में सहायता मिलती रहेगी। छठी पंचवर्शीय योजना के दौरान यह निर्ण लिया गया था कि गरीबी हटाने के विभिन्न उपायों जैसे समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन आववासन कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम की पहल की गयी। सामानिव्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्ग अब तक 84 अरब 13 करोड़ रूपये के व्यय से 2 करोड़ 54 लाख परिवार को लाभ पहुंचाया गया। इन लाभ वाले लोगों में 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोग हैं। गरीबी अन्मूलन के लिए कृषि विकास मुद्दा बनाया गया है।

सुझाव

1. आदिवासी कल्याण योजना का क्रियान्वयन और अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। परियोजना के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के मध्य प्रभावी समन्वय होना चाहि, साथ ही परियोजना के कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के बीच प्रभावी सांमजस्य होना आवश्यक हैं।
2. कामकाजी माताओं की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

संदर्भ

1. Acker Sandra. Women and education, Kagan Page, Nichols Publishing House, India, 1983, 1984.
2. Bhowmik KL. Development of women and child. Inter India Publications, New Delhi, 1985.